Liberalisation of value added services and cellular telephone service

806. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI BHUBHANESHWAR KALITA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to liberalise value-added services in the national telecommunication network;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether cellular telephone services will be permitted in cities following the liberalisation; and

(d) if so, what would be the monthly rental and call charges for that service?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) It is proposed to make available Value added services including Cellular Mobile Services in the National Telecom Network progressively. In respect of Cellular Telephone service, tenders have been invited for licensing this service to Indian companies in four metro cities, namely New Delhi, Calcutta, Bombay and Madras. In respect of other value—added services no decision has been taken so far.

(c) Yes, Sir. This service will be expanded to other cities in due course.

(d) Not yet finalised.

Amendment to Indian telegraph Act, 1885

807. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what progress has been made by the Telecom Commission and Review Committee in the matter of reporting on amendment of the outdated Indian Telegraph Act, 1885; and

(b) by when the report is finally expected?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The committee was formed in November, 1991 and held several meetings formal and informal. A draft questionnaire has also been drawn up and circulated to all the field telecom units for their comments. The Committee held a meeting at Bombay and interacted with the consumer organisations, bulk users and representatives of trade, commerce and industry to have their views on the amendment.

(b) The work on drafting the report will be taken during the remaining two months of the committee's tenure.

राज्यों की राजधानी की दूरभाष निदेशिकायें उपलब्ध कराना

808. **डा० अबरार अहमद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों तथा अजमेर, जोधपुर और कोटा के लिये 1992 तक की प्रत्येक वर्ष की दूरभाष निदेशिकायें उपलब्ध करा दी जा चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए तथा साथ ही किस वर्ष तक प्रकाशित की जा चुकी है ;

(ग) इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं और साथ ही इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जयपुर में अधिकांश दूरभाष खराब पड़े रहते हैं ;

(ङ) यदि हां तो क्या इसके कारण हैं और साथ ही इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(च) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जयपुर में 197, 198, 199 की सुविधा ठीक नहीं रहती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडु) : (क) से (छ) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

Conversion of manual exchanges at Sibsagar into electronic exchanges

809. SHRI BHADRESHWAR BURAGOHAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Sibsagar Town, although a district headquarter is not provided with an electronic exchange;

(b) whether any arrangements have been made to convert the present manual exchange into an electronic exchange; and

(c) if so, by when the conversion will be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU). (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. The existing electro-mechanical automatic (not manual) Telephone Exchange at Sibsagar is planned for replacement by an electronic exchange during 1994-95.

संचार-प्रणाली के विकास के लिए अन्य देशों के साथ किए गए करार

810. डा० अबरार अहमद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत सरकार ने संचार के साधनों को विकसित करने के लिए किन-किन देशों तथा कंपनियों के साथ करार किये हैं और ये करार कब-कब किये गये तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार उक्त करार के अधीन कुछ उपकरणों का आयात करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्राराशि खर्च की जायेगी और क्या उसके लिये सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(घ) क्या कुछ संचार साधनों तथा यंत्रों का निर्यात भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडु) : (क) जानकारी नीचे लिखे अनुसार:—

देश	करार की तारीख
जर्मन संघीय गणराज्य,	नवम्बर, 1990
यूरोपीय समुदाय का आयोग	अप्रैल, 1991
कुवैत	फरवरी, 1992

प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए संबंधित सरकारों के साथ करार किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऊपर (क) में उल्लिखित देशों को ही उपस्करों आदि का निर्यात किया जाता हो।

(ङ) जानकारी विवरण में दी गई है।